

उपलब्धि : कारोबार सुगमता में प्रदेश 12वें स्थान से दूसरे पर पहुंचा, केंद्र ने नई रैंकिंग जारी की

यूपी की लम्बी छलांग

लखनऊ/नई दिल्ली | हिटी

कारोबार सुगमता की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने इस बार लंबी छलांग लगाई है। उसने तमाम बड़े छोटे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यूपी ने यह उपलब्धि दस पायदान छलांग लगा कर पाई है। उद्यमियों के उद्योग लगाने संबंधी आवेदन का समय से निस्तारण, उनकी संतुष्टि और समस्याओं का तेजी से निपटारा-इन अहम वजहों से उत्तर प्रदेश को यह उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन को देते हुए उन्हें बधाई दी है।

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने इस बार भी अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को दिल्ली में राज्यों की रैंकिंग जारी की। केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

राज्यों की रैंकिंग

राज्य	रैंक 2017-18	रैंक 2019
आंध्रप्रदेश	1	1
उत्तर प्रदेश	12	2
तेलंगाना	2	3
मध्यप्रदेश	7	4
झारखंड	4	5
छत्तीसगढ़	6	6
हिमाचल प्रदेश	16	7
राजस्थान	9	8

(डीपीआईआईटी) द्वारा तैयार कारोबार सुगमता रैंकिंग-2019 में तेलंगाना तीसरे स्थान पर है।

रिपोर्ट को पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और घरेलू तथा वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी माहौल को सुधारना है। पिछली रैंकिंग

यूपी को पहले नंबर पर लाएंगे : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कारोबार सुगमता की रैंकिंग में राज्य की ऊंची छलांग से सिद्ध हो गया है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। भविष्य में रैंकिंग में और सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निवेशकों व जनता को बधाई देते हुए कहा कि कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए कृत संकल्पित है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उद्यमियों, निवेशकों तथा उद्योगपतियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।



➤ सभी के सहयोग से उपलब्धि पेज 02

जुलाई, 2018 में जारी हुई थी। तब आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा था। उसके बाद क्रमशः तेलंगाना और हरियाणा का स्थान रहा था। उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था।

इन मानकों पर खरा उतरना जरूरी: राज्यों को रैंकिंग कई मानकों मसलन निर्माण परमिट, श्रम नियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंच, जमीन की

उपलब्धता तथा एकल खिड़की प्रणाली के आधार पर दी जाती है।

राज्यों को क्या होता है फायदा: रैंकिंग राज्यों और संघ शासित प्रदेशों कारोबार करने की दृष्टि से बेहतर स्थान बनाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे राज्यों को और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उनका कहना है

01 नंबर पर आंध्र प्रदेश का स्थान इस बार भी बरकरार रहा

18 नंबर से लुढ़ककर 26वें स्थान पर पहुंचा बिहार

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

कारोबारी सुगमता बढ़ने की सीधा नाता नए कारोबार के अवसर बढ़ने, पुराने कारोबार का विस्तार होने और नए निवेश आकर्षित करने से है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। साथ ही इसमें प्रत्यक्ष रोजगार के मुकाबले अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होते हैं।

कि यह ऐसा माध्यम बनने जा रहा है, जो अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि एफडीआई पानी की तरह है और वह उस रास्ते पर बढ़ता है, जहां कम से कम प्रतिरोध हो। लिहाजा जितना आप प्रतिरोधों को कम करेंगे, उतना ही एफडीआई तेज होगा।

➤ कारोबारियों की संतुष्टि पर यूपी को मिली बढ़त पेज 02